

अंधेरगर्दी रकरिया पंचायत में 6 लाख की लागत से बन रही गुणवत्ताहीन रोड, मनमाने ढंग से हो रहा कार्य

निर्माणधीन सीसी सड़क ने खोली सिस्टम की पोल

डिण्डोरी, नवभारत 17 दिसंबर। डिण्डोरी जिले की पंचायतों में विकास के नाम पर जो चल रहा है, उसे अगर अंधेरगर्दी का जीवंत नमूना कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनपद डिण्डोरी की ग्राम पंचायत रकरिया के सूरजपुरा मोहल्ले में करीब 150 मीटर लंबी सीसी सड़क इस बात की गवाही खुद दे रही है कि जमीन पर कुछ और फाइलों में कुछ और चल रहा है।

पंद्रहवें वित्त आयोग से स्वीकृत करीब 6 लाख रुपये की लागत वाली यह सड़क घटिया निर्माण, बिना बेस, बिना निगरानी और बिना जिम्मेदार अफसरों की मौजूदगी में बनाई जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब काम ही मनमाने ढंग से हो रहा है,



तो गुणवत्ता की उम्मीद किससे की जाए?

मौके पर कोई जिम्मेदार नहीं

जब मौके पर मौजूद कार्य संभाल रहे व्यक्ति से निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, तो जवाब चौकाने वाला था कि हमें इसकी

कोई जानकारी नहीं है। बेस तैयार नहीं किए जाने पर वर्षों पुरानी सड़क दिखाकर कह दिया गया कि यही बेस है। न तो साइट पर वाइब्रेटर मशीन, न कोई तकनीकी निगरानी, न ही कोई शासकीय कर्मी। साफ है काम चाहे जैसा हो, बिल-बाउचर और फोटो घर बैठे तैयार होंगे।

उपयंत्र की हास्यापद जवाब

जब पंचायत के उपयंत्र से फोन पर सवाल किया गया, तो जवाब और भी हास्यास्पद रहा। उन्होंने कहा कि वहां सड़क पहले से हार्ड है। अब उपयंत्री यह भी बता दीजिए कि जब वर्षों पुरानी सड़क पहले से हार्ड थी

तो प्राक्कलन भी उसी हिसाब से क्यों नहीं किया? प्राक्कलन तो पूरा तैयार है, लेकिन काम अधूरा और नियमों से कोसों दूर है। बहरहाल यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या पंचायतों में करोड़ों रुपये इसी तरह कागजातों पर सड़क बनाकर डकार लिए जाएंगे।

इनका कहना है

आपके माध्यम से जानकारी संज्ञान में आई है और तत्काल ही कार्य रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। कल हमारे कार्यालय के जो वरिष्ठ और तकनीकी अधिकारी हैं वह जाकर के मौके का निरीक्षण करेंगे, यदि गुणवत्ता ठीक पाई जाती है तभी आगे का कार्य कराया जाएगा।

प्रमोद कुमार ओझा सीईओ, जनपद पंचायत डिण्डोरी

छात्रावास के भवन की दीवार में आई दरार

भवन का निर्माण कार्य घटिया स्तर का हो रहा है

अमरपुर नवभारत 17 दिसंबर। विकासखंड मुख्यालय अमरपुर में संचालित कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास, जोकि वर्ष 2006 से संचालित है। इस भवन निर्माण का कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग डिण्डोरी को सौंपा गया था, परंतु दो पंचवर्षीय योजना बीत जाने पर भी पूर्ण नहीं किया जा सका था।

इस अपूर्ण भवन को ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा मरम्मत कार्य कराकर विभागीय गतिविधियां संचालित की जा रही थी, परंतु विभाग द्वारा वापस लेते हुए कन्या छात्रावास का संचालन लेना। शिक्षा विभाग द्वारा कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास के लिए नया भवन स्वीकृत किया गया है। इस भवन निर्माण का कार्य एजेंसी पुलिस हाउसिंग बोर्ड होने की जानकारी प्राप्त हुई है। निर्माण



स्थल पर किसी भी प्रकार का सूचना पटल नहीं लगाया गया है, जिससे अन्य जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

उपयंत्री आज तक नहीं गए निरीक्षण करने

जानकारी के अनुसार उक्त भवन का निर्माण कार्य निम्न स्तर का हो रहा है। इसकी दीवार में अभी से ही दरार साफ दिखाई देने लगी है। जिस भवन की शुरुआत कमजोर

हो उसका भविष्य क्या होगा सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उपयंत्री द्वारा भी निर्माण कार्य का निरीक्षण नहीं किया जाता तो फिर तकनीकी मार्गदर्शन का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। उक्त भवन की लागत की जानकारी ब्लॉक श्रेत समन्वयक को भी नहीं है और न ही टेकेदार का पता है। भवन निर्माण में कोताही बरतना मतलब छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ ही कहा जा सकता है।

एक नजर में



70 महिलाओं का सफल नसबंदी ऑपरेशन

शहपुरा नवभारत 17 दिसंबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा में बुधवार को महिला नसबंदी शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें कुल 70 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया। यह शिविर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चला, जहां सुव्यवस्थित तरीके से महिलाओं की जांच एवं ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। नसबंदी शिविर के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अरविंदम गौतम द्वारा सभी महिलाओं का सुरक्षित एवं सफल ऑपरेशन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में स्वच्छता, दवाइयों और आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ऑपरेशन से पूर्व महिलाओं की आवश्यक स्वास्थ्य जांच की गई तथा ऑपरेशन के बाद उन्हें रिकवरी कक्ष में निगरानी में रखा गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने महिलाओं को आवश्यक दवाइयां देने के साथ-साथ देखभाल संबंधी दिशा-निर्देश भी दिए।

आशा कार्यक्रमों को प्रदान की प्रोत्साहन राशि-नसबंदी ऑपरेशन के उपरांत शासन की योजना के तहत महिलाओं एवं उन्हें शिविर तक लाने में सहयोग करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और मातृ स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में ऐसे शिविर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शिविर के सफल आयोजन में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं का सहकारी योगदान रहा।

बांधवगढ़ में मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक

चिल्हारी उमरिया। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में स्थित सुप्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में घूमने वाले पर्यटक अब मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पर्यटकों को कोर क्षेत्र में घूमने से पहले अपना मोबाइल बंद कर सुरक्षित रखना होगा, जिसके बाद ही वह अन्दर प्रवेश कर सकेंगे।

बता दें कि अभी तक पर्यटक अपने मोबाइल का प्रयोग कर बेहद फोटो वीडियो बना रहे थे, किंतु एक आदेश के बाद यह प्रक्रिया पूर्णतः बंद कर दी गई है। इस संबंध में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय ने बताया कि अभी वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार सभी पर्यटकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपना मोबाइल बंद करने के बाद ही कोर एरिया में दर्शन लाभ लें।

दो-तीन दिन में होगी व्यवस्था : डॉ. सहाय

डॉ. अनुपम सहाय ने बताया कि हम दो-तीन दिन के अंदर यह व्यवस्था कर लेंगे कि मोबाइल गेट के बाहर स्टॉल में सुरक्षित जमा कराए जाएंगे। इसके बाद ही पर्यटक अंदर प्रवेश कर सकेंगे। इन्होंने कहा कि कोर एरिया में भ्रमण के दौरान पर्यटक मोबाइल उपयोग करने के दौरान पूरी तरह क्षेत्र को अच्छे से देख व समझ नहीं पाते थे। पर्यटक मोबाइल में वीडियो फोटो पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते थे, किंतु अब मोबाइल उपयोग बंद होने के बाद सभी पर्यटक बांधवगढ़ क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों को अच्छे से देख और समझ सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया जा रहा पालन

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर को दिए गए आदेश के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) शुभ्रजन सेन ने बीते दिन आदेश जारी किए हैं, जिसमें सभी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक को पत्र लिखा है कि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कोर पर्यटन क्षेत्र में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाए, जिसका पालन अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है।

शासकीय स्कूलों में घट रही छात्रों की संख्या

बच्चों को शासन दे रहा कई सुविधाएं, फिर भी छात्र नहीं पहुंच रहे स्कूल

चिल्हारी नवभारत 17 दिसंबर। जिले में इन दिनों शासकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, जो कि चिन्ता का विषय है, जबकि शासन द्वारा बच्चों को भोजन, कपड़े, किताब के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इसके बाद भी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या कम दिखती है।

बताया जाता है कि इसमें कुछ कमियां विद्यालय के शिक्षकों की हैं, साथ ही छात्र छात्राओं के माता-पिता अभिभावकों की भी हैं, जो अपने बच्चों को समय से स्कूल नहीं भेजते तथा घरेलू कार्यों में बच्चों को व्यस्त कर देते

हैं, जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और बच्चे बुरी संगत में पढ़कर गलत मार्ग में चले जाते हैं। तब अभिभावकों को स्कूल की याद आती है।

स्कूलों का स्तर सुधारना होगा

विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या कम होने के कारण शिक्षकों का भी मन नहीं लगता और अपना दिन पूरा कर घर चले जाते हैं। यदि सभी अभिभावक अपने बच्चों को समय से स्कूल भेजे और समय समय पर बच्चों की निगरानी रखें तो निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर सुधर सकता है।

शासन द्वारा इतनी सुविधाएं देने केबाद भी अगर स्कूलों का शिक्षा स्तर नहीं सुधरता तो चिन्ता का विषय है। इस पर सभी सामाजिक व्यक्तियों को चिन्तन करना चाहिए।



तेज रफ्तार कार पलटी, 3 की मौत

दो घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी

नवभारत उमरिया 17 दिसंबर। जिले के नगर परिषद मानपुर अंतर्गत खरीदी केंद्र सिगुडी में समय पर धान परिधान का उठाव नहीं हो रहा व ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं।

खरीदी केंद्र सिगुडी में धान रखने जगह नहीं

समय पर धान का उठाव नहीं होने से किसान परेशान

चिल्हारी उमरिया 17 दिसंबर। जिले के नगर परिषद मानपुर अंतर्गत खरीदी केंद्र सिगुडी में समय पर धान परिधान का उठाव नहीं हो रहा व ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं।

खरीदी केंद्र सिगुडी के राजकुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि खरीदी केंद्र सिगुडी में इतनी अधिक मात्रा में धान रखी हुई है कि

धान रखने की जगह नहीं बची। दूसरी ओर इस कड़ाके की ठंड में किसान धान लेकर आते हैं तो जगह नहीं मिलने के कारण किसानों को भारी मशकत करनी पड़ती है। शासन के निर्देशानुसार खरीदी केंद्र सिगुडी में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण किसान अपने वाहन से धान तो ले आते हैं, लेकिन रखने की जगह ही नहीं है। किसानों ने मांग की है कि खरीदी केंद्र सिगुडी में समय पर धान का उठाव कराया जाए।

लंबित प्रकरणों का शीघ्र किया जाए निराकरण : वर्मा

जनपद पंचायत शहपुरा में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

शहपुरा नवभारत 17 दिसंबर। जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ऐश्वर्य वर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद क्षेत्र की विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में समस्त ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पंचायत समन्वयक अधिकारी एवं संबंधित योजना प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान धरती आबा जनभागीदारी अभियान, सीएम हेल्पलाइन, लेबर बजट, समग्र ई-केवाईसी, सूचना



का अधिकार, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, 'एक बगियाचा के नाम' योजना तथा जनपद भूमि आवंटन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई।

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें-एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों

को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, लंबित प्रकरणों का समय-समय पर निराकरण करने तथा सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना प्राथमिकता होनी चाहिए।

को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, लंबित प्रकरणों का समय-समय पर निराकरण करने तथा सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना प्राथमिकता होनी चाहिए।

तनातनी

जिला पंचायत डिण्डोरी में टकराव चरम पर, मामला कार्यों की राशि जारी करने और एक बगियाचा के नाम योजना के तहत लगाए जा रहे पौधों की गुणवत्ता को लेकर

अध्यक्ष व सीईओ आमने-सामने, अभद्रता के आरोप, मामला पहुंचा पुलिस तक

डिण्डोरी, नवभारत 17 दिसंबर। जिला पंचायत डिण्डोरी में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी के बीच तनातनी खुलकर सामने आ गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परसे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) दिव्यांशु चौधरी के बीच हुई तीखी कहासुनी अब पुलिस जांच का विषय बन गई है।

दोनों पक्षों की शिकायत के बाद मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया है, जिससे जिला मुख्यालय में राजनीतिक-प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार 17 दिसंबर को जिला पंचायत कार्यालय में निर्माण कार्यों की राशि जारी करने और एक बगियाचा के नाम योजना के तहत



लगाए जा रहे पौधों की गुणवत्ता को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि इसी मुद्दे पर अध्यक्ष और सीईओ के बीच बातचीत ने उग्र रूप ले लिया।

सीईओ का गंभीर आरोप

सीईओ दिव्यांशु चौधरी ने पुलिस को दिए लिखित आवेदन

में आरोप लगाया है कि वे अपने कार्यालय कक्ष में शासकीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, तभी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परसेत उनके कक्ष में पहुंचे और निर्माण कार्यों की राशि शीघ्र जारी कराने का दबाव बनाने लगे। सीईओ के अनुसार उन्होंने पहले ही इस विषय पर चर्चा के

लिए 22 दिसंबर की तिथि तय कर दी थी, इसके बावजूद अध्यक्ष ने तेज आवाज में बात की, टेबल टोकरी, गाली-गलीज की और धमकी दी। सीईओ ने यह भी कहा कि इस घटनाक्रम से उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

अध्यक्ष ने मांगे सीसीटीडी फुटेंट

उक्त मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परसेत ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिण्डोरी के नाम पत्र प्रेषित कर लेख किया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा दूरभाष पर 12:30 कार्यालय

बुलाने पर जब वह कार्यालय पहुंचे तो वहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उनके साथ अभद्रता पूर्वक बात की। जिसके सी सी टी व्ही फुटेज की वह मांग कर रहे हैं।

इनका कहना है

मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें अध्यक्ष पर अभद्रता, गाली-गलीज और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है।

वाहिनी सिंह पुलिस अधीक्षक, डिण्डोरी